अब एटीएम चार्ज खत्म करने की तैयारी में आरबीआई, रिव्यू के लिए बनाया पैनल

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। रिजर्व बैंक ने एनईएफटी और आरटीजीएस पर लगने वाले चार्ज खत्म करने के बाद अब बैंकिंग कस्टमर्स को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आरबीआई ने मंगलवार को ऑटोमेटेड टेलर मशींस के इस्तेमाल पर लगने वाले चार्जेस और फीस की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन किया है। आरबीआई की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक, यह कमेटी पहली मीटिंग के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। इसी महीने हुई बाई-मंथली मॉनिट्री पॉलिसी में केंद्रीय बैंक ने कहा था कि एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एटीएम सुविधा से वंचित क्षेत्रों में एटीएम फैसिलिटी को बढ़ावा देना था। आरबीआई ने डेवलपमेंटल और रेग्युलेटरी पॉलिसीज पर जारी बयान में कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अध्यक्षता में बना पैनल एटीएम चार्जेस और फीस की समीक्षा करेगा। इस कमेटी में आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव वी जी कन्नन के अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ दिलीप अस्वे, एसबीआई के सीजीएम गिरि कुमार नायर, एडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड (लायबिलिटी प्रोडक्ट्स) एस सम्पत कुमार, कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री के डायरेक्टर के श्रीनिवास और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस के सीईओ संजीव पटेल शामिल हैं।

दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरु

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। दिल्ली सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए की तरह के काम कर रही है। इस दिशा में दिल्ली के ऊर्जा मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 स्थित बीएसईएस के ग्रिड में पहले स्मार्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। एक पैनल में दो गाड़ियां चार्ज की जा सकती हैं। एक बार चार्जिंग के लिए लोगों को 160-200 रुपए तक देने होंगे। कार वालों को 1.60 रुपये/किलोमीटर से 1.80 रुपये/किलोमीटर खर्च आएगा। यह अपनी तरह का अनोखा कांसेप्ट है, जो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करेगा। इलेक्ट्रीफाइ नाम के मोबाइल ऐप पर वाहन मालिक ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनका नजदीकी चार्जिंग स्टेशन कौन सा है और किस चार्जिंग स्टेशन पर अभी चार्जिंग पोर्ट खाली है या चार्जिंग के लिए कितनी वेटिंग है। यही नहीं, वेटिंग से बचने के लिए वे वहां पर जाने से पहले ही अपने लिए एक चार्जिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और उसके लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था इस लिए की गई है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों का समय बचे और चार्जिंग स्टेशन पर जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत न हो। ऑनलाइन अग्रिम भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई और भीम ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। बीएसईएस के सीईओ अमल सिन्हा के अनुसार, दिल्ली में करीब 2500 इलेक्ट्रिक कारें हैं। उन्हें चार्ज करने के लिए ही कंपनी ने साउथ एक्स पार्ट-2 में चार्जिंग के दो पैनल लगाए हैं।

दालों में लगी आग, अरहर दाल के दाम 100 रुपए के पार

नई दिल्ली,12 जून (ए)। आम आदमी को अब दाल की महंगाई सताने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली के रिटेल मार्केट में अरहर दाल की कीमतें 100 से 120 रुपए प्रति किलो के भाव तक पहुंच गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अरहर दाल की कीमतें उत्पादन में कमी की वजह से बढ़ी है। वहीं, इस साल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, इसीलिए कीमतों में तेजी है। हालांकि, सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के पास दाल की कोई कमी नहीं है। कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसकी जांच होगी। सरकार ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से 1.75 लाख टन अरहर दाल के आयात की अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 लाख टन अरहर दाल आयात के लिए जल्द लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

सरकार करेगी जांच: कंज्यूमर अफेयर्स सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि देश में अरहर की दाल पर्याप्त मात्रा में है। मौजूदा समय में करीब 14 लाख टन का बफर स्टॉक है। इसके बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही है। इसकी जांच जल्द की जाएगी।

अरहर दाल क्यों हो रही है महंगी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांग बढ़ने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरहर दाल के दाम बढ़े हैं। साथ ही, दुनिया के बड़े अरहर दाल उत्पादक कई देशों में भी उत्पादन घटने के बाद कीमतों में तेजी आई है। भारत म्यांमार से अरहर की दाल खरीदता है। इससे पहले साल 2015 में पहली बार भाव 200 रुपए किलोग्राम के पार पहुंच गया था। भारत के अलावा म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों में ही अरहर दाल पैदा होती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल देश में अरहर की दाल का 40 लाख टन से ज्यादा उत्पादन हुआ था। वहीं, इस साल ये 35 लाख टन के करीब है। पिछले खरीफ सीजन में अरहर दाल की बुआई कम हुई थी। इसके अलावा सरकार ने दालों के आयात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस साल मानसून कमजोर रहने की संभावना से भाव चढ़े हैं। आल इंडिया दाल मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट सुरेश अग्रवाल का कहना है कि दो महीने में इंपोर्टेड दाल भारत में आ जाएंगी। अगर आयात में देरी हुई तो दालों के दाम और ऊपर जाएंगे।

बजट में कारोबारियों के लिए हो सकता है वेलफेयर फंड का ऐलान, वेयरहाउस ग्रिड पर भी हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली,12 जून (ए)। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में कई योजनाओं का ऐलान किया था। चुनावों में शानदार जीत के बाद भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में उन वादों का जिक्र किए जाने की संभावना है, जो घोषणापत्र में किए गए थे। इन वादों में जल जीवन मिशन, मत्स्य संपदा योजना, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड और वेयरहाउसिंग ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उम्मीद है कि इस बजट में इन योजनाओं को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा और बजट का आवंटन किया जाएगा।

पिछले बजट से थोड़ा ही अधिक होगा इस बजट का आकार: बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट टार्गेट को जीडीपी का 3.4 फीसदी रखने का लक्ष्य बनाया है। 2019-20 के अंतरिम बजट का साइज 27.84 लाख करोड़ रुपए था, इस बजट का साइज उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा। जल शक्ति मंत्रालय, मत्यपालन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री इन सभी स्कीम्स के खर्च और बजट में आवंटन तय करने के लिए बैठक करने जा रहे हैं।

मत्स्य संपदा योजना: घोषणापत्र में मत्य संपदा योजना का ऐलान किया गया था। इसके तहत पारंपरिक मछुआरों की सुविधा के लिए आइस-बॉक्स, कोल्ड स्टोरेज, आइस-प्लांट जैसे भंडारण और मार्केटिंग के साधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इस योजना के तहत सरकार जलकृषि (एक्वा कल्चर) को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण मुहैया कराएगी।

वृद्धि दर के 2011-17 के आंकड़े 2.5 प्रतिशत बढ़ा-चढ़ाकर आंके गए

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धिदर) की गणना के लिए अपनाए गए नए पैमानों के चलते 2011-12 और 2016-17 के बीच आर्थिक वृद्धि दर औसतन 2.5 प्रतिशत ऊंची हो गई। उन्होंने हार्वर्ड विश्विद्यालय द्वारा प्रकाशित अपने शोध पत्र में कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर उपरोक्त अवधि में 4.5 प्रतिशत रहनी चाहिए जबकि आधिकारिक अनुमान में इसे करीब 7 प्रतिशत बताया गया है।

सुब्रमणियम ने कहा, ''भारत ने 2011-12 से आगे की अवधि के जीडीपी के अनुमान के लिए आंकड़ों के स्रोतों और जीडीपी अनुमान की पद्धति बदल दी है। इससे आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अच्छा-खासा ऊंचा हो गया। जीडीपी की नई श्रृंखला के तहत देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर विवाद के बीच यह रिपोर्ट आई है। तौर-तरीकों की समीक्षा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई। उन्होंने कहा, ''आधिकारिक अनुमान के अनुसार सालाना औसत जीडीपी वृद्धि 2011-12 और 2016-17 के बीच करीब 7 प्रतिशत रही। हमारा अनुमान है कि 95 प्रतिशत विश्वास के साथ इसके 3.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में मानते हुए इस दौरान जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही होगी। सुब्रमणियम लिखते हैं कि विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही तरीके से आकलन नहीं किया गया। वह पिछले साल अगस्त में आर्थिक सलाहकार पद से हटे। हालांकि उनका कार्यकाल मई 2019 तक के लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह है, ''वृहत आर्थिक नीति काफी बड़ी है। सुधारों को आगे बढ़ाने की गति संभवत: कमजोर हुई। आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाना प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए, जीडीपी अनुमान पर फिर से गौर किया जाना चाहिए।

भारतीय युवक की निकली 10 लाख डॉलर की लॉटरी

दुबई, 12 जून (ए)। ओमान में रहने वाले भारतीय व्यक्ति की 'दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलियनेयर्स ड्रॉ में 10 लाख डॉलर की लॉटरी निकली है। खलीज टाइम्स ने खबर दी है कि रघु कृष्णामूर्ति 10 लाख डॉलर की लॉटरी जीतने वाले 143वें भारतीय बन गए हैं। उन्हें अबतक इस बारे में जानकारी नहीं है। साल 1999 में शुरू हुई 'दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलियनेयर प्रोमोशनज्' पांच हजार टिकट निकालती है और एक व्यक्ति को 10 लाख डॉलर जीतने का मौका होता है। घोषणा के बाद, पिछले विजेता 40 साल के भारतीय नागरिक रतीश कुमार रवींद्रन नायर के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनकी भी 10 लाख डॉलर की लॉटरी निकली थी। इसके अलावा दो भारतीय नागरिकों को बीएमडब्ल्यू मोटरबाइक मिली हैं।

ट्राई ने टाटा टेलीसर्विसेज को उपभोक्ताओं की बची राशि लौटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) को प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की बची राशि तथा पोस्टपेड उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है। कंपनी द्वारा प्रशासनिक तरीके से आर्वटित स्पेक्ट्रम को छोड़ने तथा 16 सर्किलों में सेवाएं बंद करने के बाद नियामक ने यह निर्देश दिया है।

ट्राई ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में उपभोक्ताओं द्वारा अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने से पहले शेष प्रीपेड राशि खर्च कर दी जाती लेकिन इस मामले में स्पेक्ट्रम को समय से पहले सरेंडर किए जाने की वजह से टीटीएसएल के सीडीएमए मोबाइल ग्राहकों को या तो पोर्ट करना पड़ा या अपने मोबाइल नंबर को गंवाना पड़ा। ऐसे में उन्हें प्रीपेड की बची हुई राशि और सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि वापस नहीं मिली।

ट्राई ने टीटीएसएल को पोर्ट किए गए मोबाइल नंबरों पर खर्च नहीं हुई प्रीपेड राशि को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने टीटीएसएल द्वारा घोषित 'सनसेट तिथि 28 फरवरी, 2019 के आगे सेवाएं नहीं ली हैं और वे अपने नंबर को पोर्ट नहीं कर पाए हैं उनके खाते में शेष बची राशि भी लौटाने का निर्देश दिया गया है। नियामक ने सोमवार को टीटीएसएल को निर्देश दिया कि वह सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि का लौटाने की प्रक्रिया शुरू करे और 20 अगस्त, 2019 तक प्राधिकरण को लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों के आधार पर अनुपालन की जानकारी दे।

अनिल अंबानी का दावा, 14 महीनों में चुकाया 35 हजार करोड़ रुपए का कर्ज

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के प्रमुख अनिल अंबानी ने कहा कि उनका समूह सभी ऋण देनदारियों को समय से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 14 महीनों में उनके समूह ने 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है।

अंबानी ने कि चुनौतीपूर्ण हालातों और वित्तपोषकों से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने के बावजूद उनके समूह ने एक अप्रैल, 2018 से लेकर 31 मई, 2019 के बीच अपने ऊपर बकाया ऋण में 24,800 करोड़ रुपए मूलधन और 10,600 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया है। उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ हफ्तों के दौरान गैर-वाजिब अफवाहों, अटकलों और रिलायंस समूह की सभी कंपनियों के शेयर में गिरावट के चलते हमारे सभी हितधारकों को काफी नुकसान हुआ है। यह 35,000 करोड़ रुपए के ऋण का भुगतान रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इनसे संबद्ध कंपनियों से जुड़ा है।

अंबानी ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनका समूह भविष्य में सभी ऋण देनदारियों को समय से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उसके पास परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण की योजना है जिसे वह कई स्तर पर लागू भी कर चुका है। अंबानी ने समूह की कुछ समस्याओं के लिए नियामकीय संस्थानों और अदालतों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फैसला आने में देरी की वजह से समूह को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया नहीं मिल पाया। अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और उससे संबद्ध कंपनियों का यह बकाया पांच से 10 साल तक पुराना है। इस पर अंतिम निर्णय आने में एक के बाद एक कारणों से देरी हुई। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रणाली ने समूह के प्रति पूरी तरह उदासीनता बरती और कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि इसने ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों के हितों का नुकसान हुआ। अंबानी ने भरोसे से कहा कि समूह को बदलने की यात्रा शुरू हो चुकी है जिसमें पूंजी को हल्का रखने, कम से कम ऋण लेने और शेयर पर ऊंचा रिटर्न देने की प्रतिबद्धता है जो सभी हितधारकों के मूल्य को बढ़ाएगा।

यात्री वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट, कई दिग्गज कंपनियों ने रोका कारों का प्रोडक्शन

नई दिल्ली, 12 जून (ए)। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 18 साल की सबसे अधिक गिरावट आई है। कार बनाने वाली कंपनियों को पैसेंजर व्हीकल की डिमांड में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड में कमी के कारण हजारों गाड़ियां शोरूम में खड़ी हैं। कार की बिक्री में कमी को लेकर सबसे बड़ी वजह जीएसटी का स्लैब बताया जा रहा है। इसके अलावा देश में नौकरी की धीमी गति, तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी कार की मांग में गिरावट देखने को मिली है।

कई बड़ी ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने अपने पिछले प्रोडक्शन के स्टॉक को खत्म करने के लिए फिलहाल अपने प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। इन कंपनियों ने जून के महीने में प्लान्ट को कुछ दिनों के लिए शटडाउन करने की घोषणा की है। कंपनी अगर ज्यादा दिन तक शटडाउन होती है तो कई लोगों के नौकरी जाने का भी खतरा हो सकता है। इस सेक्टर से भारी संख्या में कामगार जुड़े हुए हैं। वहीं, मई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री 20.55 प्रतिशत घटकर 2,39,347 वाहन रह गई। मई 2018 में यह आंकड़ा 3,01,238 वाहन था। खास बात यह है कि पिछले 11 में से 10 महीनों में यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। सिर्फ अक्टूबर 2018 ही ऐसा रहा जब यात्री वाहनों की बिक्री में 1.55 प्रतिशत की बढ़ौतरी दर्ज हुई थी। पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट सितम्बर 2001 के बाद सबसे अधिक रही है। उस समय यात्री वाहनों की बिक्री 21.91 प्रतिशत घटी थी। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार मई में सभी प्रमुख खंडों- दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन

में वाहनों की बिक्री में गिरावट आई। मई में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 26.03 प्रतिशत घटकर 1,47,546 इकाई रह गई। पिछले साल मई में यह आंकड़ा 1,99,479 इकाई था। इसी तरह समीक्षाधीन महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री 4,.89 प्रतिशत घटकर 11,62,373 इकाई रह गई, जो पिछले साल पहले समान महीने में 12,22,164 इकाई थी। मई में दोपहिया की कुल बिक्री 6.73 प्रतिशत घटकर 17,26,206 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 18,50,698 इकाई थी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मई में 10.02 प्रतिशत घटकर 68,847 इकाई रह गई। मई 2019 में विभिन्न श्रेणियों में सभी वाहनों की बिक्री 8.62 प्रतिशत घटकर 20,86,358 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 22,83,262 इकाई थी।

52,000 करोड़ रुपए के 35 लाख वाहनों को नहीं मिल रहे खरीदार

देश की 10 शीर्ष कार और टू-व्हीलर निर्माता कम्पनियों में से 7 ने घोषणा कर दी है कि वे कई दिनों तक अपने मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट्स बंद रखने वाली हैं। कम्पनियों ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कार और टू-व्हीलर्स की कम बिक्री के चलते उनकी इन्वैंट्री अब तक बिकी नहीं है। कम्पनियां पहले उन वाहनों को बेचना चाहती हैं, उसके बाद नए वाहनों की मैन्यूफैक्चरिंग की जाएगी। इस कदम से भले ही कम्पनियों को अपनी इन्वैंट्री खाली करने में मदद मिलेगी लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने ग्रोथ टार्गेट पूरे नहीं कर पाएगी। एक समाचार के मुताबिक जून की शुरूआत में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की कीमत के 5 लाख पैसेंजर व्हीकल्स और 17.5 हजार करोड़ के 30 लाख टू-व्हीलर डीलरशिप्स में खड़े हैं, लेकिन उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहा है। प्लांट बंद करने वाली कम्पनियों में मारुति-सुजुकी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा व टाटा मोटर्स शामिल हैं। इन कम्पनियों ने मई से जून के बीच अपने प्लांट बंद रखे हैं। मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट्स के बंद होने से मई-जून के बीच इंडस्ट्री का आऊटपुट 20-25 प्रतिशत तक घटने की आशंका है लेकिन असल घाटा हो रहा है डीलर्स को, जिनकी इन्वैंट्री में सामान्य से 50 प्रतिशत तक अधिक वाहन रखे हैं। उन्हें इन वाहनों पर जी.एस.टी. चुकाना पड़ रहा है।

मारुति ने मई में वाहन उत्पादन में की 18 प्रतिशत की कटौती

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति-सुजुकी इंडिया (एम.एस.आई.) ने मई महीने में वाहन उत्पादन में 18 प्रतिशत की कटौती की है। यह लगातार चौथा महीना है जब कंपनी ने उत्पादन में कटौती की है। मारुति-सुजुकी ने कहा कि उसने मई 2019 में हल्के वाणिज्यिक वाहन समेत कुल 1,51,188 वाहनों का उत्पादन किया जबकि एक साल पहले इसी महीने कंपनी ने 1,84,612 इकाइयों का उत्पादन किया था। इस दौरान उत्पादन में 18.1 प्रतिशत की कटौती की गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहन (एल.सी.वी.) सुपर कैरी को छोड़कर कंपनी ने मई में कॉम्पैक्ट और मिनी कारों सहित अन्य सभी वाहन श्रेणियों में उत्पादन में कमी की है। मारुति ने आल्टो, रिवाइट और डिजायर समेत यात्री वाहनों का उत्पादन 18.88 प्रतिशत घटा कर 1,48,095 वाहन कर दिया। मई 2018 में उसने 1,82,571 इकाइयों का उत्पादन किया था।